मैं परमपावन दलाई लामा से बिना पासपोर्ट के कैसे मिलीः वूएजर

(हाईपीक्सप्योरअर्थ, 13 जनवरी, 2011)

सात साल पहले अपने निबंध संग्रह "नोट्स ऑन टिबेट" में मैने एक ग्रुप फोटो के बारे में लिखा था, जिसमें एक पिता अपने पुत्र के साथ ल्हासा से धर्मशाला की ओर चुप–चाप जाते हुए दिख रहे थेः" वे जो दोनों तरफ नम्रता और शालीनता का वातावरण बनाते हैं, लेकिन केंद्र का आलिंगन करते हैं, वह सभी धर्मपरायण तिब्बती लोगों में से सबसे ज्यादा विख्यात हैं,सबसे ज्यादा स्नेहमय और उत्सुक व्यक्ति–दलाई लामा।" इस वाक्य और सच को छूने वाले कुछ लेख लिखने के कारण, स्थानीय अधिकारियों ने मेरे काम को "गंभीर राजनीतिक गलतियों" वाला बताया जिसमें 14वें दलाई लामा और 17वें करमापा लामा की तारीफ की गई थी और गंभीर राजनीतिक एवं धार्मिक विचारों को बढ़ावा देने जैसी गलत बात थी। यह कहा गया कि कुछ निबंध कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से गलतियों वाले हैं।" मुझे मेरे पद से हटा दिया गया, इसके बाद मैंने ल्हासा छोड़ दिया। इसके पहले भी करीब 16 साल पहले मैंने एक कविता लिखा था जिसका निहितार्थ यह थाः''सड़क पर, मैंने एक फूल तोड़ा जो इस दुनिया का नहीं था, उसके मुरझाने से पहले, सभी दिशाओं में इसकी खोज के बाद, ताकि गहरे लाल कपड़ों वाले बुजुर्ग आदमी को इसे पेश कर सकूं। वह आदमी मनोकामना को पूरा करने वाला एक हीरा है, मुस्कराहट की एक रेखाः जो पीढ़ियों को मजबूती से बांधे हुए है।'' बाद में मैंने इस कविता को गीत में बदल दिया और इसमें खुलकर कहा कि 'गहरे लाल कपड़ों में बुजुर्ग आदमी' हमारे येशी नोर्बू हैं, हमारे कुनदुन, हमारे गोनसाछोग, हमारे ग्यालवा रिनपोछे...'' ये सब दलाई लामा के लिए कहे जाने वाले सम्मानसूचक शब्द हैं।जैसे कि बहुत सारे तिब्बतियों की आकांक्षा होती है कि परमपावन को देख पाएं, सम्मानपूर्वक उनके उपदेश सुनें, उनके दर्शन पाएं। काफी कम उम्र से मेरे भी अंतर्मन की यही इच्छा रही है, मैं हमेशा से लालायित रही हूं कि यह सपना सच हो। लेकिन मुझे पासपोर्ट नहीं मिला, जैसा कि बहुत से अन्य तिब्बतियों को नहीं मिलता, यह लगभग अकल्पनीय है कि यह सरकार जो हम पर नियंत्रण रखती है कभी हमें पासपोर्ट देगी, जो कि वास्तव में हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए।

पिछले साल ल्हासा प्रशासन ने 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को पासपोर्ट दिया, लेकिन यह व्यवस्था भी सिर्फ एक हफ्ते रही। इसकी वजह से पासपोर्ट इंचार्ज के कार्यालय में भूरे बालों वाले लोगों की भीड़ लग गई, बुजुर्गों की तरह धीरे–धीरे चलते लोग और यह बात साफ थी कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने, बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और एक ऐसा सपना पूरा करने के लिए हिमालय की चोटियों की ओर जा रहे हैं जिसके बारे में कोई बोल नहीं सकता, लेकिन हर कोई जानता है। मैं दुखी मन से यह सोच रही थी कि क्या मुझे 60 वर्ष की उम्र होने तक एक पासपोर्ट हासिल करने का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इंटरनेट ने मेरे पासपोर्ट विहीन जीवन को यात्रा की एक स्वीकृत दे दी,नए साल में इसने मेरे सपने को साकार करने में मदद की। इंटरनेट के माध्यम से मैं परमपावन दलाई लामा से मिली,वह जैसे सपने में आए हों, लेकिन थे काफी जीवंत और वास्तविक! यह दर्शन साइबर दुनिया में वीडियो संवाद के साथ शुरू हुआ। गत 4 जनवरी, 2011 को परमपावन धर्मशाला में थे और चीन के दो मानवाधिकार वकीलों तेंग बियाओ और जियांग तियानयोंग और लेखक वांग लिजियोंग के साथ वीडियो संवाद में लगे थे। और मैं, मैं वांग लिजियोंग के पीछे खड़ी थी, इस संवाद के हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। जब दलाई लामा स्क्रीन पर आए तो मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह चमत्कार तकनीकी क्रांति की वजह से हो पाया था, इसने भौगोलिक दूरियों और मानव निर्मित बाधाओं से पार पाना संभव कर दिया था और ऐसा सेतु बनाया था जिससे दलाई लामा चीनी बुद्धिजीवियों से बात कर पा रहे थे। निस्संदेह यह एक बेहद महत्वपूर्ण क्रांति है। मैंने सुना परमपावन तीन चीनी बुद्धिजीवियों से कह रहे थेः "यह ऐसा ही लग रहा है जैसे हम सब साथ हों, हम बस केवल एक–दूसरे की सांसों को नहीं सूंघ सकते।" करीब 70 मिनट तक चली बातचीत के अंत में दिलचस्पी भरी आवाज में परमपावन ने पूछा, "क्या आप मुझे साफ तौर पर देख पा रहे हैं?" जब तीनों लोगों ने कहा, कि हां वे उन्हें साफ–साफ देख रहे हैं, तो उन्होंने हास–परिहास के अंदाज में अपने भौंहों की तरफ इशारा किया और हंसते हुए पूछाः "तो क्या आप मेरे भूरे भौंहों को भी देख पा रहे हैं?" मैं रोती रही और रोती रही। जब मैंने, जैसा कि तिब्बती करते हैं, तीन बार साष्टांग प्रणाम किया, मन ही मन कुछ मंत्र पाठ किया,अपने हाथों में खाता लिए और अश्रुपूरित नेत्रों के साथ कंप्यूटर के सामने घुटनों के बल बैठे हुए, तो मैंने देखा कि परमपावन ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए जैसे कि वे खाता ग्रहण करने जा रहे हों, जैसे कि वे मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हों। मेरे पास यह बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं कि मैं कैसा महसूस कर रही थी... ।वास्तव में मैं तिब्बत में कितनी भाग्यशाली व्यक्ति थी, जबकि बहुत से लोग सिर्फ दलाई लामा के फोटो रखने की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

सच तो यह है कि आज समूचे चीन से बहुत से लोग परमपावन से मिल रहे हैं और उनकी कोई आज़ादी नहीं छीनी गई है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, इसलिए तिब्बतियों को भी परमपावन के दर्शन के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। स्क्रीन पर मेरी तस्वीर की ओर मुखातिब होते हुए दलाई लामा ने मुझे गंभीर और अथक तरीके से निर्देश दियाः "हिम्मत मत हारो, प्रयास जारी रखो, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हान चीनी बुद्धिजीवी और हम तिब्बती हमेशा एक–दूसरे को उस असल हालात के बारे में बताएं जिस पर हम बात कर सकते हैं और एक–दूसरे को समझ सकते हैं, आपको इसका आंतरिक तौर पर प्रयास करना चाहिए। पिछले 60 साल से तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों का साहस और भरोसा चट्टान की तरह मजबूत है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत के हालात पर गहराई से नजर रखे हुए है, पूरी दुनिया के लोग यह देख रहे हैं कि तिब्बत में सचाई है, चीनी बुद्धिजीवी भी लगातार इस बारे में जागरूक हो रहे हैं, इसे व्यापक नजरिए से देख रहे हैं, बड़ा और ताकतवर चीन बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसलिए आपको आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आप समझ रहे हैं न? तब तक मैं शांत हो चुकी थी और मैंने परमपावन द्वारा कहे गए शब्दों को अपने दिल में संजो कर रख लिया।

बीजिंग, 5 जनवरी, 2011

तिब्बती संस्कृति कर्मी ल्हासा में गिरफ्तार और रिहा

इस नीति की घोषणा के बाद अक्टूबर, 2010 में पूरे प्रांत के हजारों तिब्बती छात्र विरोध स्वरूप सड़कों पर उतर आए थे। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सितंबर 2010 में धार्मिक मामलों के राज्य प्रशासन के आदेश संख्या 8 'तिब्बती बौद्ध मठों एवं मंदिरों के प्रबंधन उपाय' द्वारा चीन तिब्बतियों की धार्मिक आज़ादी पर और अंकुश लगाया जा रहा है।

(टिबेटनरीव्यूडॉटनेट, 13 जनवरी)

तिब्बत में जन्में और चामदो प्रशासनिक क्षेत्र के पेलबार काउंटी में रहने वाले लेखक तेनपा लोदोए को 29 दिसंबर, 2010 को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें उसी दिन रिहा भी कर दिया गया। लोदोए की शिक्षा कार्जे काउंटी में स्थित निंगमा मठ में हुई है और उन्होंने तिब्बती संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए पूरे तिब्बत का भ्रमण किया है। युवा भिक्षु तेनपा लोदोए 'घांग गा ख्यामपो' (मुक्त जीवट यायावर) के नाम से लिखते हैं। जन सुरक्षा ब्यूरो के जवानों ने उन्हें उनके एक दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। खबरों के अनुसार लोदोए और उनके दोस्त को तब गिरफ्तार किया गया जब वे ल्हासा के मुख्य चौराहे पर थे। उन्हें एक थाने में ले जाया गया और एक पूछताछ वाले कुर्सी पर बांध दिया गया। इस कुर्सी में हाथ–पांव को जकड़ने वाला ढक्कन लगा था। लोदोए की सभी व्यक्तिगत चीजें जैसे लैपटॉप, मोबाइल, फोन, किताबें, प्रिंटर, बौद्ध धर्मग्रंथ और प्रिटिंग ब्लॉक को पुलिस ने जब्त कर लिया। उनको हिरासत में लेने की वजह का पता नहीं चल पाया है और न ही यह पता है कि अभी वह कहां हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि उनकी बहन को उनसे ल्हासा के एक कारावास में हाल में मिलने दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोदोए ने एक पत्रिका 'वाक फॉरवर्ड' (आगे बढ़ो) का संपादन किया है, वह बुद्धिजीवियों के एक स्वतंत्र काउंटी शिक्षा परामर्श समिति 'पालबार सोकपा' के सदस्य हैं और पूर्वी तिब्बत के युवा भिक्षुओं एवं लेखकों द्वारा स्थापित संगठन गांग्री नेबाब सोकपा (बर्फीले पर्वत प्रतिष्ठा संघ) के संस्थापक रह चुके हैं। पुरग्याल की नामशे (तिब्बत के प्राचीन राजाओं की आत्मा) नामक पत्रिका के संपादक एवं भिक्षु दोस्त गोयोन और कई अन्य तिब्बती लेखकों के साथ लोदोए ने तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में कई सम्मेलनों और चर्चाओं का आयोजन किया।

इनमें सिचुआन की राजधानी चेंगदू में 24 जनवरी को 'सोमरिग घी दाकवांग सोलवा (साहित्यिक कॉपीराइट की तलाश) विषय पर लेखकों का एक सम्मेलन भी शामिल है जिसमें 17 तिब्बती संपादक, ब्लॉगर और लेखक शामिल हुए। हाल में लोदोए ने 20 दिसंबर, 2010 को कार्जे प्रशासन के पालयुल काउंटी के ताशी देलेक होटल में घांग्री नेबाव लेंगवा (बर्फीली जमीन की हालत पर चर्चा) विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। लोदोए ने दो किताबें 'गा मियुल दो धुए (जब मैं विदेश गया)' और 'जेन वॉग घी चिमिग (एक भिक्षु के शाल के नीचे की पश्चदृष्टि) लिखी हैं और इसके अलावा इंटरनेट पर उनके कई निबंध एवं लेख प्रकाशित हुए हैं।

चीन ने 831 तिब्बतियों को बनाया है राजनीतिक बंदी

(टिबेटनरीव्यू डॉट नेट, 14 जनवरी)

चीनी शासन के तहत दिसंबर, 2010 तक तिब्बती राजनीतिक बंदियों की संख्या बढ़कर 831 हो गई है। इनमें से 360 को न्यायालय से सजा दी गई है और 12 को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के दौरान 188 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 71 को अदालतों द्वारा सजा सुनाई गई।

रिपोर्ट के अनुसार साल 2008 के बाद 60 से ज्यादा तिब्बती लेखकों, ब्लॉगर, बुद्धिजीवियों

और संस्कृति कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अनुसार साल 2008 के वसंत के बाद से नौ तिब्बतियों को मौत की सजा सुनाई गई जिसमें से दो को तो फांसी दे दी गई, जबकि अन्य की सजा दो साल के लिए विलंबित रखी गई है। साल 2010 चामदो प्रशासन के कोलु मठ में रहने वाले सोनम सेरिंग और लामा लाका को मौत की सजा सुनाई गई।

रिपोर्ट में तिब्बत में जारी चीन की शिक्षा नीति की भी आलोचना की गई है, खासकर क्विंघई प्रांत के सरकार के उस आदेश का जिसमें कहा गया है कि साल 2015 तक सभी प्राइमरी स्कूलों के पाठ और पुस्तकें चीनी भाषा में होनी चाहिए। इससे सिर्फ तिब्बती और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई को ही छूट दी गई है। इस नीति की घोषणा के बाद अक्टूबर, 2010 में पूरे प्रांत के हजारों तिब्बती छात्र विरोध स्वरूप सड़कों पर उतर आए थे। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सितंबर 2010 में धार्मिक मामलों के राज्य प्रशासन के आदेश संख्या 8 'तिब्बती बौद्ध मठों एवं मंदिरों के प्रबंधन उपाय' द्वारा चीन तिब्बतियों की धार्मिक आज़ादी पर और अंकुश लगाया जा रहा है।

यह आदेश एक नवंबर से ही प्रभावी हो गया है। इस आदेश के अनुसार तिब्बत के ध ार्मिक केंद्रों का किसी भी विदेशी धर्मगुरू से संपर्क रखने को अवैध करार दे दिया गया है। तिब्बत में विकास एवं आधुनिकता की नीति के माध्यम से चीन जरूरत आधारित रवैए को नजरअंदाज कर रहा है जिससे तिब्बती चरवाहे एवं किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

दलाई लामा का उपदेश सुनने वाले तिब्बती को जेल में डाला गया

(टिबेटनरीव्यूडॉटनेट, 17 जनवरी)

साल 2008 में भारत की यात्रा और दलाई लामा से धार्मिक उपदेश सुनने वाले तिब्बत के नागचू प्रशासन के ड्रिरू काउंटी के एक नागरिक को हाल में दो साल के लिए जेल में डाल दिया गया। 29 साल के चिमे ताशी को कब और क्यों सजा सुनाई गई इसकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्हे उनके घर से 3 अक्टूबर, 2010 को गिरफ्तार किया गया था।

इसके पहले भी जब वह साल 2005 में 50 अन्य तिब्बतियों के साथ भारत की तीर्थयात्रा के लिए नेपाल की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हे नेपाल के सीमावर्ती कस्बे सोलुखुंभू में पकड़ लिया गया था। तब सभी लोगों को चार महीने के लिए धिंगरी और शिगास्ते में कठोर श्रम वाले कारावास में रखने के बाद उनके संबंधित काउंटी की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। चिमे उन 30 लोगों में थे जो ड्रिरू लाए गए और पुलिस ने हर व्यक्ति से 4,000 युआन की जमानत लेकर उन्हें रिहा कर दिया था। लेकिन इसके बाद साल 2008 में सीमा पार करने में सफल रहा छिमे भारत के बोधगया और वाराणसी गया जहां दलाई लामा के उपदेश सुने। बताया जा रहा है कि फिलहाल उसे ल्हासा के तोलुंग डेछेन काउंटी में स्थित एक कारावास में रखा गया है और ऐसे संकेत हैं कि उसे अदालत ने नहीं बल्कि एक प्रशासनिक निकाय के आदेश पर सजा दी गई है।

उन्होंने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जिस तरह से लगातार अपमानित होना पड़ रहा है उस पर प्रध ाानमंत्री और विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। हम भारतीय हैं और केंद्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश पर साफ नीति बनानी चाहिए।"

चीनी अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर तिब्बती भिक्षु ने आत्महत्या की

(टिबेटनरीव्यूडॉटनेट, 21 जनवरी)

साल 2007 में दलाई लामा से मुलाकात की वजह से असहनीय प्रताड़ना झेलने वाले उत्तरी तिब्बत के सॉग काउंटी में रहने वाले

"पूर्वी हिस्से सहित समूचे चीन–भारत सीमा मसले पर चीन की स्थिति सुसंगत और साफ है और भारतीय पक्ष इस बात को अच्छी तरह जानता है।"

एक भिक्षु ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ओस्लो से वायस ऑफ टिबेट रेडियो सर्विस ने 18 जनवरी को यह खबर दी है। खबर के अनुसार 48 साल के लोबसांग पालडेन 15 नवंबर, 2010 को नागचू प्रशासन के त्रिडो टाउनशिप में स्थित द्रधेल मठ में मृत पाए गए। स्थानीय धार्मिक मामलों के ब्यूरो के चीनी अधिकारियों ने उन्हें लगातार प्रताड़ित किया था और दलाई लामा से उनके कथित संपर्कों को लेकर उन्हें लगातार धमकी दी जाती रही।

इन सबकी वजह यह थी कि उन्होंने साल 2007 में परमपावन से मुलाकात की थी। मौत से पहले उनसे अधिकारियों ने लगातार कई घंटे पूछताछ की थी और उनको मठ से बाहर करने की धमकी दी गई थी।

चीन के नत्थी वीजा पर अरुणाचल में विरोध

चीनी सैनिकों ने एक शेड बना रहे भारतीय मजदूरों को धमकाया और काम रोकने को कहा, जबकि यह शेड ग्रामीण विकास विभाग की इजाजत से बन रहा था।

(पीटीआई, 13 जनवरी)

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा अरुणाचल के दो निवासियों को नत्थी वीजा देने के मसले पर राज्य में भारी विरोध हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में आल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) ने चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ का पुतला फूंका। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया।

चीन विरोधी नारे लिखे तख्तियां लिए हुए सैंकड़ों आपसू कार्यकर्ताओं ने राजधानी के प्रमुख केंद्र बांक टिनाली में कई घंटों तक चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि अरुणाचल निवासी भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (आईडब्ल्यूएफ) के संयुक्त सचिव अब्राहम के.तेची और भारोत्तोलक युकर सिबी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमिग्रेशन अधिकारियों ने वापस भेज दिया था क्योंकि उनके पास चीनी दूतावास द्वारा दिया हुआ नत्थी वीजा था। इस मसले को गंभीरता से न लेने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए आपसू के अध्यक्ष तकाम तातुंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत की 'गलत विदेश नीति' से पीड़ित हो रहा है।

उन्होंने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जिस तरह से लगातार अपमानित होना पड़ रहा है उस पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। हम भारतीय हैं और केंद्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश पर साफ नीति बनानी चाहिए।" तातुंग ने कहा कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार को तिब्बत मसले को गंभीरता से उठाना चाहिए। दूसरी तरफ, संसद सदस्य और हाल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने तापिर गावो ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इसके बदले में चीन से भारत आने वाले लोगों को भी नत्थी वीजा दे।

सीमावर्ती ग्रामीणों ने दिया चीनी सैनिकों के सीमा उल्लंघन के सबूत

(13 जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया)

सीमावर्ती ग्रामीणों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के चीनी सैनिकों द्वारा उल्लंघन के ऐसे पुख्ता सबूत दिए हैं जिसे नकारना चीन के लिए आसान नहीं होगा। भारत सरकार चीनी सैनिकों के बार–बार सीमा उल्लंघन पर आंख मूंदे बैठी हुई है, लेकिन एलएसी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि इन क्षेत्रों में विकास न होने की वजह से ही वहां चीन के लिए धौंस जमाना आसान हो गया है। एलएसी से थोड़ी दूर पर स्थित एक छोटे से गांव के ग्रामीणों ने बताया कि चीनी सैनिक आसानी से सीमा पार कर इस तरफ आ जाते हैं और धीरे–धीरे वे 1962 के

भारत–चीन युद्ध के बाद निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा को भी बदल रहे हैं। इस गांव में रहने वाले एक चरवाहा कालजांग पोंछोक ने बताया, "हालांकि काफी समय ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन गर्मियों में वे आसानी से इधर आ जाते हैं और हमारे देश की सीमा के भीतर एक से डेढ़ किलोमीटर अंदर तक आ जाते हैं।"

एक अन्य नागरिक सेरिंग धोनडुप ने बताया, "चीन से यह कहना चाहिए कि वह शांत रहे और अपनी सीमा के भीतर रहे। उन्होंने तिब्बत पर कब्जा जमाया, सात अन्य देशों पर कब्जा जमाया। हम भारतीय हमेशा शांत बने रहे। लेकिन हम कब तक चुप्पी रख सकते हैं? पिछले साल सितंबर–अक्टूबर में चीनी सैनिकों के जम्मू–कश्मीर के देमोछोक क्षेत्र के गोमबीर इलाके में घुस जाने की खबरें आई थीं। चीनी सैनिकों ने एक शेड बना रहे भारतीय मजदूरों को धमकाया और काम रोकने को कहा, जबकि यह शेड ग्रामीण विकास विभाग की इजाजत से बन रहा था। हालांकि थल सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह का कहना है कि ऐसे 'तथाकथित' घुसपैठ चीन और भारत के बीच एलएसी के बारे में अवधारणात्मक मतभेदों की वजह से होते हैं और इस मसले का समाधान दोनों देश बातचीत से करने की कोशिश कर रहे हैं।

चीन ने कहा, उसकी अरुणाचल नीति में कोई बदलाव नहीं

(इकनॉमिक टाइम्स, 17 जनवरी)

चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को 'विवादास्पद क्षेत्र' मानने की उसकी नीति में 'कोई बदलाव' नहीं आया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिणी तिब्बत' बताता रहा है और कुछ दिनों पहले ही उसने इस राज्य के दो खिलाड़ियों को नत्थी वीजा दिया था।चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, "पूर्वी हिस्से सहित समूचे चीन–भारत सीमा मसले पर चीन की स्थिति सुसंगत और साफ है और भारतीय पक्ष इस बात को अच्छी तरह जानता है।"

गौरतलब है कि भारत–चीन सीमा के पूर्वी खंड में अरुणाचल प्रदेश भी आता है जो वार्ता प्रक्रिया का भी हिस्सा है। भारत और चीन अब तक इस मसले को हल करने के लिए 14 दौर की वार्ताएं कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। अरुणाचल प्रदेश के दो भारतीय खिलाड़ियों को चीन के फूजियान प्रांत में आयोजित वेटलिफ्टिंग ग्रैंड पिक्स में हिस्सा लेने के लिए जाने पर चीन ने नत्थी वीजा दिया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इस बारे में पिछले हफ्ते पत्रकारों द्वारा सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है। हालांकि चीन पहले यह कहता था कि अरुणाचल प्रदेश तो उसका हिस्सा है, इसलिए वहां के लोगों को चीन जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन अब चीन नत्थी वीजा दे रहा है। तो क्या चीन ने अपने पहले की नीति को छोड़ दिया है, इस बारे में भी विदेश मंत्रालय का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

हालांकि, सरकार द्वारा संचालित चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर रिसर्च फेलो रोंग यिंग ने कहा कि इस विवाद पर चीन के पक्ष में कोई बदलाव नहीं आया है, शायद नत्थी वीजा देकर चीन सरकार ने एक 'व्यावहारिक' कदम उठाया है ताकि अरुणाचल प्रदेश के लोग चीन की यात्रा कर सकें। इस इंस्टीट्यूट में भारत विशेषज्ञ रोंग ने पीटीआई को बताया, "निश्चित रूप से हमने वास्तविकता को ध्यान में रखा है क्योंकि यह एक विवादास्पद क्षेत्र है और यदि वहां के लोग चीन की यात्रा करना

'मैप वर्ल्ड' नाम की यह सेवा इंटरनेट पर चीनी भाषा में दिख रही है और चीन में आईफोन एवं अन्य मोबाइल तथा इंटरनेट यूजर अप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए उसे 'दक्षिण तिब्बत' के रूप में दिखाता है।

लेकिन चीन साफतौर पर इस संगठन से बहुत डरा हुआ है।

चाहते हैं तो हमें व्यावहारिक होना होगा।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन लोगों की यात्रा को सुगम बनाना अच्छा होगा, अन्यथा जब तक यह विवाद हल नहीं हो जाता उस क्षेत्र के लोग चीन की यात्रा नहीं कर पाएंगे।

चीन ने नई मानचित्र सेवा में अरुणाचल, अक्साई चिन को अपना हिस्सा बताया

संयुक्त राष्ट्र के इस कदम से चीनी अधिकारियों को अच्छा बहाना मिल गया है जब भी वे 'कोई हमला करें तो उन्हें कुचल दिया जाए।' झांग को पूरी उम्मीद है कि चीन अब संयुक्त राष्ट्र की बांह मरोड़कर उससे टीवाईसी को भी आतंकवादी समूह घोषित कर देगा।

(पीटीआई, 18 जनवरी)

चीन ने सरकारी मानचित्र वेबसाइट की आधिकारिक रूप से शुरुआत की है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को उसने अपना हिस्सा दिखाया है। यह मानचित्र सेवा चीन सरकार ने गूगल अर्थ के मुकाबले में शुरू की है।

'मैप वर्ल्ड' नाम की यह सेवा इंटरनेट पर चीनी भाषा में दिख रही है और चीन में आईफोन एवं अन्य मोबाइल तथा इंटरनेट यूजर अप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए उसे 'दक्षिण तिब्बत' के रूप में दिखाता है। इस मानचित्र सेवा में अक्साई चिन को भी चीन के सीक्यांग प्रांत का हिस्सा बताया गया है, जबकि यह भारत में लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। ये दोनों क्षेत्र दोनों देशों के बीच चलने वाले सीमा विवाद वार्ताओं का भी हिस्सा रहे हैं। इस बारे में दोनों देशों में अब तक 14 दौर की वार्ता हो चुकी है। सीमा के ये अनसुलझे मुद्दे चीन–भारत संबंधों में लंबे समय तक बनी रही कड़वाहट की भी वजह रहे हैं।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ का दावा है कि 'यह ऑनलाइन मानचित्र सेवा आधिकारिक, भरोसेमंद और एकीकृत मानचित्रण पेश करने के लिए है।'

इस मानचित्र सेवा की शुरुआत के मौके पर चीन की एसबीएसएम के उप निदेशक मिन यिरेन ने पत्रकारों को बताया इस वेबसाइट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक आंकड़े हासिल किए जा सकते हैं और चीन के बारे में तो काफी 'विस्तृत' आंकड़े मौजूद हैं जिसमें चीन के ग्रामीण इलाकों के गांवों, कस्बों के बारे में भी विवरण मिलता है।

चीन को तिब्बत में मिला 24.6 लाख टन लीथियम भंडार

(टिबेटनरीव्यूडॉटनेट, 18 जनवरी)

चीन को तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में करीब 24.6 लाख टन लीथियम कार्बोनेट का एक खान मिला है। चीन ने कहा है कि इससे देश में लीथियम उत्पादन की लागत घटेगी और उसके नवीन ऊर्जा उद्योग को काफी मदद मिलेगी।

सरकारी चाइना डेली अखबार ने कहा है कि इस खोज की जानकारी चीन के भूमि एवं संसाधन उप मंत्री वांग मिन ने 15 जनवरी को बीजिंग में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया है। हालांकि इस खबर में यह जानकारी नहीं दी गई है कि तिब्बत मे किस जगह पर यह खोज की गई है। मंत्री ने यह भी बताया है कि तिब्बत के पठार में स्थित क्विंगतांग घाटी के यिन घाटी में तेल एवं गैस का बड़ा भंडार है। उन्होंने क्विंघई प्रांत के क्विलान पहाड़ के पास जमी हुई जमीन के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट की खोज का हवाला देते हुए कहा कि नए ऊर्जा संसाधनों की खोज में यह एक बड़ी उपलब्धि है।

वांग ने कहा कि भूवैज्ञानिकों के प्रयास की वजह से पिछले 10 साल में जो नए संसाधन खोजे गए हैं (इनमें से ज्यादातर तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में हैं) वह पिछली आधा सदी में खोजे गए कुल संसाधनों के करीब पचास

फीसदी के बराबर होगा। हर साल नए संसाधनों की इतनी ज्यादा खोज हो रही है यह वार्षिक खपत से भी ज्यादा हो गया है। मंत्री ने बताया कि चीन कोयला, इस्पात, अल्युमिनियम, तांबा और सीमेंट का दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

लेकिन इसे अपने पेट्रोलियम एवं लोहे की खपत का आधा से ज्यादा हिस्सा, तांबा खपत का करीब 70 फीसदी हिस्सा और सिल्वाइट खपत का करीब 64 फीसदी हिस्सा आयात करना पड़ता है।

तिब्बत के चीनी मुखिया को सता रहा है स्वतंत्रता संघर्श का भूत

(टिबेटनरीव्यू डॉट नेट, 28 जनवरी)

तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) के चीनी प्रमुख झांग क्विंगली ने कहा कि तिब्बत के कथित अलगाववादी ताकतों से निपटना सीक्यांग प्रांत के उइगर से निपटने से ज्यादा जटिल है और इसके लिए अलग रणनीति की जरूरत है। ये वही महाशय हैं जिन्होंने साल 2008 में कहा था कि दलाई लामा भिक्षु के वेश में भेड़िया हैं जिनका दिल जानवर का है।

चीन के सरकारी अंग्रेजी अखबार चाइना डेली में 26 जुलाई को छपे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, "तिब्बत में अलगाववादी ताकतों जैसे तिब्बती यूथ कांग्रेस से अलग तरीके से निपटा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी तक आतंकवादियों के रूप में नहीं देखा जाता है।'' गौरतलब है कि तिब्बती यूथ कांग्रेस (टीवाईसी) को चीन सरकार एक आतंकवादी गुट मानती है, लेकिन इस संगठन के चीन के खिलाफ किसी हिंसक अभियान में शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, न ही इस संगठन की चीनी शासन वाले तिब्बत की कहीं मौजूदगी पाई गई है। लेकिन चीन साफतौर पर इस संगठन से बहुत डरा हुआ है। इसकी व्यापक पहचान और तिब्बत की पूर्ण आज़ादी के लिए साफतौर पर इसके खड़े होने की वजह से। चीन के दबाव में आकर संयुक्त राष्ट्र ने विवादास्पद रूप से सीक्यांग की आज़ादी के लिए लड़ने वाले दि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (टीईटीआईएम) को एक आतंकवादी गुट घोषित कर दिया है, जबकि इस बात कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यह संगठन किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा हो।

संयुक्त राष्ट्र के इस कदम से चीनी अधिकारियों को अच्छा बहाना मिल गया है जब भी वे 'कोई हमला करें तो उन्हें कुचल दिया जाए।' झांग को पूरी उम्मीद है कि चीन अब संयुक्त राष्ट्र की बांह मरोड़कर उससे टीवाईसी को भी आतंकवादी समूह घोषित कर देगा। झांग को साल 2005 में टीएआर में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। इसके पहले वह छह साल तक सीक्यांग में अपनी 'सेवाएं' दे चुके हैं।

गुवाहाटी में 7 सितंबर को गिरफ्तार यूएनएलएफ नेता निंगोमबम दिलीप उर्फ इबोचो के लैपटॉप की जांच करने पर यह जानकारी सामने आई।

भारत में पकड़े गए तीन चीनी नागरिक जासूस नहीं : चीन सरकार

(पीटीआई, 21 जनवरी)

चीन सरकार ने कहा है कि बिना वैध दस्तावेज के भारत में हाल में पकड़े गए तीन चीनी नागरिक जासूस नहीं बल्कि 'पर्यटक' हैं जो 'गलती' से भारतीय सीमा क्षेत्र में चले गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के अनुसार एक महिला समेत इन तीनों लोगों को भारत–नेपाल सीमा पर अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने और महत्वपूर्ण संस्थानों का फोटो खींचते हुए पकड़ा गया था। लियाओ जिंग, यू दांगली और यांग लिउ नाम के इन तीनों चीनी नागरिकों को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने उत्तर प्रदेश में रुपइडिहा बॉर्डर

देश में अवैध तरीके से घुसने के लिए उन्हें पासपोर्ट कानून के तहत जेल में डाल दिया गया।

(1)

(2)

(10)

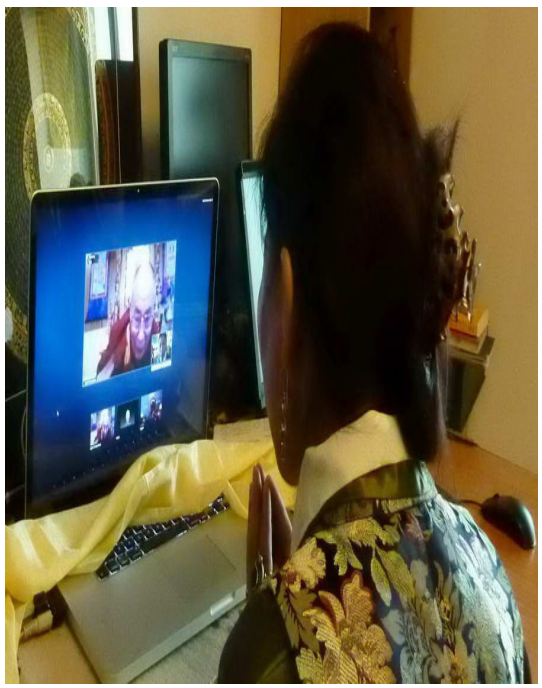

कैमरे की

1. अपने को अर्द्ध रिटायर व्यक्ति बताने वाले दलाई लामा ने हाल में कहा है कि हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि
2. धर्मशाला में 7 जनवरी, 2011 को आयोजित 5वें अखिल भारतीय भारत–तिब्बत ग्यालवांग कर्मापा और ग्यारी डोलमा।
3. बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय में तिब्बती छात्रों द्वारा आयोजित तिब्बत जाग एक तिब्बती छात्र।
4. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 जनवरी, 2011 को भारत–तिब्बत मैत्री समाज की नवांग ल्हामो (दाएं से तीसरी) महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों के साथ।
5. 56 साल के मंगोल आंदोलनकारी हदा। हदा को 15 साल तक जेल में बंद र पुत्र यूइलेस को भी बंदी बना लिया गया।
6. चीन में मानवाधिकार के प्रमुख वकील और राजनीतिक कैदी गाओ झिशेंग की सम्मेलन को संबोधित करते हुए। इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि क्रिस स्मिथ ग
7. यह उन तस्वीरों में से एक तस्वीर है जिसमें यह दिखाया गया है कि चीनी दिया जा रहा है। यह फोटो एक तिब्बती कार्यकर्ता द्वारा चुपके से लिया गया
8. बार्सिलोना में 22 जनवरी, 2011 को एनएफए की बैठक के दौरान टीएनएसए
9. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कनवर्जेंट जर्नलिज्म के छात्रों द्वा के नई दिल्ली स्थित प्रतिनिधि कालोन तेम्पा सेरिंग। फोटोः जावेद सुल्तान
10. परमपावन दलाई लामा और दो चीनी कार्यकर्ताओं के बीच 4 जनवरी, 2011 को वूजर। फोटो–हाईस्पीकप्योरअर्थ

(9)

(8)

(3)

(4)

आंख से

वह राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों से 'पूरी तरह रिटायर' होने की सोच रहे हैं, वह तिब्बती जनता के स्वतंत्रता संघर्ष से पूरी तरह अलग हो जाएंगे।
कॉलेज विद्यार्थी सम्मेलन के दौरान (दाएं से बाएं) प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे,

रूकता सप्ताह के दौरान लोगों को तिब्बत से जुड़ी तस्वीरों के बारे में जानकारी देता

पहली बैठक के दौरान निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति की सदस्य सुश्री

खने के बाद 10 दिसंबर को रिहा करना था, लेकिन उसी दिन उनकी पत्नी जिना और

पत्नी गेंग ही 18 जनवरी, 2011 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में एक संवाददाता
ाओ का पोर्ट्रेट पकड़े दिख रहे हैं।
ाष्ट्रपति हू जिनताओ के स्वागत के लिए भीड़ जुटाने के लिए कई लोगों को पैसा
। (लिसा फैन– द इपोच टाइम्स)
को प्रजेंटेशन देते पूज्यनीय वांगचेन।
रा तिब्बत पर आयोजित दो दिवसीय सत्र को संबोधित करते परमपावन दलाई लामा

हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हाथ जोड़े खड़ीं तिब्बती लेखिका

(5)

(7)

(6)

पर 17 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ये लोग भारतीय सीमा में स्थित कई महत्वपूर्ण संस्थानों की तस्वीरें ले रहे थे। उनके पास एक भारतीय पैन कार्ड, दो मोबाइल फोन और एक कैमरा पाया गया। देश में अवैध तरीके से घुसने के लिए उन्हें पासपोर्ट कानून के तहत जेल में डाल दिया गया।

पाकिस्तान को देने वाली सैन्य सहायता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न होने दे चीनः भाजपा

(पीटीआई, 22 जनवरी)

"पाकिस्तान सरकार आतंकवाद का सहयोग कर रही है और सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित कर रही है। इस तरह चीन अगर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है इसका मतलब यह है कि वह भी आतंकवाद का समर्थन कर रहा है।"

भारतीय जनता पार्टी ने चीन से अनुरोध किया है कि वह अपने 'अच्छे संपर्कों' का इस्तेमाल कर 'सदाबहार दोस्त' पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव बनाए कि वह भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को रोके।

भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने 21 जनवरी को चीनी नेताओं के साथ अपनी वार्ता में उनसे कहा कि चीन जो भी मदद पाकिस्तान को कर रहा है चाहे वह नाभिकीय रिएक्टर हो या सैन्य सहायता, इस बात की पूरी संभावना है कि 'उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है।' गडकरी ने कहा, "पाकिस्तान सरकार आतंकवाद का सहयोग कर रही है और सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित कर रही है। इस तरह चीन अगर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है इसका मतलब यह है कि वह भी आतंकवाद का समर्थन कर रहा है।"

चीनी नेताओं के साथ बातचीत के बाद जारी बयान में गडकरी ने कहा कि चीन अब भी लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा किए हुए है और इसके अलावा कश्मीर में 5,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन इसे पाकिस्तान से तोहफे में मिल गया है। उन्होंने इन खबरों पर भी चिंता जताई कि चीनी सेना के जवान पाक अधिकृत कश्मीर में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने इस बात की जांच कराई और इसकी पुष्टि भी हो गई कि चीन की जनमुक्ति सेना के जवान इस इलाके में पहुंच चुके हैं।"

उत्तर–पूर्व में अलगाववादियों को सहयोग दे रहा है चीन

(द टेलीग्राफ, 30 जनवरी)

चीन की कथित जासूस वांग क्विंग को भारत से जाने की इजाजत दे दी गई, जबकि भारत को यह साक्ष्य मिला है कि चीन उत्तर–पूर्व के अलगाववादियों से यह जानकारी हासिल कर रहा है कि भारत लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें कहां तैनात कर रहा है। खुफिया सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्रों ने बताया कि साल 2010 की शुरुआत में ही सरकार को यह पता चला था कि चीन ने अपने परंपरागत सहयोगी एनएससीएन – आईएम के अलावा उत्तर–पूर्व के अन्य आतंकवादी गुटों से भी संपर्क बढ़ा दिया है और कई आतंकवादी गुटों को प्रशिक्षण दे रहा है।

सितंबर माह में सरकार को यह पता चला कि मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट से चीन ने कहा है कि वह यह जानकारी हासिल करे कि भारत ने चीन को निशाना बना कर लंबी दूरी की मिसाइलें कहां–कहां तैनात कर रखी हैं।

गुवाहाटी में 7 सितंबर को गिरफ्तार यूएनएलएफ नेता निंगोमबम दिलीप उर्फ इबोचो के लैपटॉप की जांच करने पर यह जानकारी सामने आई। लगभग इसी समय नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (इसाक–मुइवा), उल्फा, यूएनएलएफ और

दो अन्य आतंकवादी संगठनों के शीर्ष नेता चीन के ग्वांगझू में एक बैठक में शामिल हुए थे।

सूत्रों के अनुसार इसके कुछ समय पहले ही वांग ने भारत की यात्रा की थी और वह अवैध रूप से नगालैंड भी गई थी। इसके बाद वह इस माह दोबारा भारत आई और 18 जनवरी को नगालैंड के दीमापुर में पकड़ ली गई। 21 जनवरी को वांग को चीन भेज देने के बाद पिछले हफ्ते भारत ने वहां की सरकार को इस पर कार्रवाई रिपोर्ट दी और 'नाराजगी' जाहिर की।

इस रिपोर्ट में कहा गया कि वांग को गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसे तीन दिन में ही छोड़ दिया गया। इससे पता चलता है कि भारत सरकार किस तरह से चीन के साथ मसले उठाने से हिचकती है। हाल में यह खबर आई कि उल्फा नेता परेश बरुआ अप्रैल, 2009 से ही चीन के यून्नान प्रांत में रह रहा है।

मई, 2009 के पहले हफ्ते में एक शीर्ष नगा अलगाववादी नेता की चीन के यून्नान प्रांत में स्थित कनमिंग के एक होटल में रिटायर्ड चीनी जनरल ली से मुलाकात हुई थी, इसी प्रकार यून्नान के ही रुइली में एक यूएनएलएफ नेता लांचा की चीनी अधिकारियों से मुलाकात हुई।

चीन ने पिछले साल मार्च में म्यांमार के लाइजा में उल्फा को शिविर बनाने में मदद की थी और इसके बाद उसे सलाह दिया कि वह अपने 100 काडर को पश्चिमी से पूर्वी कछिन की ओर ले जाए।

सूत्रों के अनुसार एनएससीएन (खापलांग), यूनएलएफ, मणिपुर के पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) और कई अन्य मणिपुरी एवं नगा आतंकवादी समूहों ने चीन सरकार के सहयोग से उत्तरी म्यांमार के जंगलों में अपने अड्डे और प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं।

39 साल की वांग 1 जनवरी को दिल्ली पहुंची थी। उसने अपने आपको एक चीनी लकड़ी कंपनी का कर्मचारी बताया था, लेकिन खुफिया सूत्रों का कहना है कि इसके बाद वह हांगकांग के टीवी पत्रकार के साथ नगा आतंकवादी नेता मुइवा से मिली। वांग ने बिना इजाजत के छद्म नाम से नगालैंड की यात्रा की और वह हेबरॉन स्थित एनएससीएन–आईएम के मुख्यालय भी गई।

उन्होंने कहा कि साल 2013 तक 1,85,500 नए परिवारों को नए घरों में बसाया जाएगा।

नेपाल में अपने पंजे फैला रहा है चीन

(31 जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया)

चीन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। इसने पूरे नेपाल में अपना संचार नेटवर्क (टेलीफोन उपकरण कंपनी हुवेई टेक्नोलॉजी) फैलाया है। भारत–नेपाल सीमा पर तैनात खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन को इससे दो फायदे हैं।

पहला, नेपाली नागरिक इससे सस्ते फोन कॉल कर पाएंगे जिससे नेपाल के घर–घर में उसकी अच्छी छवि बनेगी। इससे भारत के पड़ोसी देश पर चीन को अपना दीर्घकालिक प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। दूसरा, चीन के पास यह सुविधा हो जाएगी कि वह नेपाल के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों, नेताओं और उद्योगपतियों की टेलीफोन पर होने वाली बातचीत का विवरण हासिल कर सके। सूत्रों के अनुसार भारत से नेपाल या नेपाल से भारत को की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण टेलीफोन कॉल पर चीन की नजर होगी। इससे उसे भारत के खिलाफ नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। नेपाल और भारत में माओवादियों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए चीन ने शैक्षणिक नेटवर्क का भी जाल बिछाया है। दोनों देशों के मुख्य माओवादी नेताओं को नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में चीनी

नेपाल में माओवादियों के सत्ता न हासिल कर पाने और भारत में माओवादी विद्रोह को दबा देने के बाद अब चीन ने नेपाल में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं।

करीब आधे दिन तक चले मुकदमे में तीनों लेखकों कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

भाषा पढ़ाई जा रही है। खुफिया सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार चीनी भाषा इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि दोनों देशों के माओवादी नेता आपस में चीनी भाषा में बात कर सकें और भारतीय खुफिया एजेंसियों को चकमा दे सकें। गौरतलब है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास चीनी भाषा जानने वाले कर्मचारी बहुत कम हैं।

खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन सरकार भारत और नेपाल में माओवादी आंदोलन भड़काने के खेल में लगी हुई है। नेपाल में माओवादियों के सत्ता न हासिल कर पाने और भारत में माओवादी विद्रोह को दबा देने के बाद अब चीन ने नेपाल में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं।

तीन लाख तिब्बती परिवारों को नए जगह बसने पर मजबूर किया गया

हालांकि चतुर चीन कुछ दिखावटी रियायतें दे सकता है, लेकिन भारत की मुख्य चिंता 'सीमा विवाद' पर कुछ नही होने वाला।

(टिबेटनरीव्यूडॉटनेट, 18 जनवरी)

साल 2006 में शुरू हुए एक 'नए देहात' कार्यक्रम के तहत तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र की स्थानीय चीन सरकार ने करीब 3 लाख परिवारों को नए या स्थायी मकानों में बसाया है जिनमें 1.43 लाख तिब्बती चरवाहे भी हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने क्षेत्रीय सरकार के अध्यक्ष पदमा छोलिंग के हवाले से यह जानकारी दी है। ल्हासा में क्षेत्रीय पीपुल्स कांग्रेस चल रही है जिसमें पिछले पांच साल के विकास की समीक्षा की जा रही है। इस कांग्रेस में ही छोलिंग ने यह रिपोर्ट दी है।

उन्होंने कहा कि साल 2013 तक 1,85,500 नए परिवारों को नए घरों में बसाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल 15 से 23 दिसंबर की अपनी चीन यात्रा के बाद खाद्य अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ओलिवर डी शटर ने कहा कि घुमंतू जातियों को ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ दिया जा रहा है, 'जहां उनके पास अपने पशुओं को बेचने और नए जगह बसने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।'

उन्होंने कहा कि चीन शासित तिब्बत एवं आंतरिक मंगोलिया में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके भोजन के अधिकार का उल्लंघन है। गौरतलब है कि तिब्बती घुमंतू जातियों, खासकर क्विंघई प्रांत के लोगों ने शिकायत की है कि जबरन नई जगह बसाने के कार्यक्रम में खाली ईंटों के मकान और शुरु में 'वार्षिक भुगतान' के बाद ज्यादातर को बिना किसी सहारे या सरकारी सहायता के छोड़ दिया जाता है।

किसानों के लिए बनाई गई नई आवासीय योजनाएं भी काफी विवादास्पद रही हैं क्योंकि इससे किसानों को बाहर से अच्छे दिखने वाले पर अंदर से घटिया मकानों के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है और इस तरह से वे कर्ज के जाल में भी फंस जा रहे हैं। सरकारी नियंत्रण वाला यह कार्यक्रम वास्तव में दुष्प्रचार के लिए ज्यादा है।

साल 2015 तक तिब्बत में हर साल आएंगे 1.5 करोड़ पर्यटक

(टिबेटनरीव्यूडॉटनेट, 15 जनवरी)

चीन ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) में हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या साल 2015 तक बढ़कर इस क्षेत्र की मौजूदा 30 लाख से कम जनसंख्या की पांच गुना से भी ज्यादा हो जाएगी। शिनहुआ समाचार एजेंसी ने 13 जनवरी को खबर दी है कि करीब 1.5 करोड़ पर्यटकों की यह संख्या मौजूदा पर्यटकों के दोगुने से ज्यादा हो जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार यह चाहती है कि 'टीएआर के सभी लोग पर्यटन की वजह से धनी हो जाएं' और वह ग्रामीण

क्षेत्रों में भी पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी जहां 80 फीसदी तिब्बती रहते हैं, इनमें से बहुत से लोग बिजली, स्वच्छ पेयजल और पक्की सड़कों से वंचित हैं।

जेल में बंद तिब्बती लेखकों से कराया जा रहा है कठोर श्रम

(रेडियो फ्री एशिया, 25 जनवरी)

'देश के बंटवारे के लिए लोगों को उत्तेजित करने' के आरोप में जेल में बंद तीन तिब्बती लेखकों ने जब अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ अपील करने से इनकार कर दिया तो उन्हें ऐसे जेल में भेज दिया गया जहां बहुत कठोर श्रम करवाया जाता है। सूत्रों के अनुसार जांगसे दोनखो, बुद्ध और कालसांग जिनपा को गत 30 दिसंबर को अबा (तिब्बती में गबा) माध्यमिक जन न्यायालय द्वारा तीन से चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्हें ऊपरी अदालत में अपील के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन माध्यमिक न्यायायल में मुकदमे के दौरान इन लेखकों को कोई वकील नहीं मुहैया किया गया और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य को कोर्ट में आने दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस मामले की सुनवाई करने वाले जज ने कहा कि इन युवा लेखकों को सजा देने का हुक्म 'ऊपर' से आया है।

एक सूत्र ने बताया कि ये तीनों लेखक चीन के दक्षिण–पश्चिमी सिचुआन प्रांत के नागबा तिब्बत स्वायत्तशासी प्रशासन के हैं और उन्हें हाल में ही नागबा के बखम कारावास केंद्र से हटाकर सिचुआन में स्थित मियान यांग जेल में ले जाया गया है। इन तीनों लेखकों को पहले जून एवं जुलाई, 2010 में ही गिरफ्तार किया गया था और उन पर देश का बांटने का आरोप इस बिना पर लगाया गया था कि उन्होंने साल 2008 में हुए रक्तरंजित तिब्बती विरोध प्रदर्शनों के बारे में एक स्थानीय न्यूजलेटर शार डुंगरी (पूर्वी बर्फीला पहाड़) में जबर्दस्त लेख लिखे थे। करीब आधे दिन तक चले मुकदमे में तीनों लेखकों कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

तिब्बत पर भारत के नरम रवैए से चीन इस मामले पर और ढीठ हुआ है।

तिब्बत नीति पर भारत को करना चाहिए पुनर्विचार

(बिजनेस स्टैंडर्ड, 25 जनवरी)

अजय शुक्ला

चीन ने निश्चित रूप से सीमा विवाद के मसले पर भारत को हाशिए पर ला दिया है। जम्मू–कश्मीर पर अपनी स्थिति को सख्त करते हुए अब चीन यह कह रहा है कि जब तक इस पर कोई और निर्णय नहीं हो जाता वह इसे पाकिस्तान का हिस्सा मानता रहेगा। इसलिए अब भारत के लिए भी यह समय आ गया है कि वह अपनी तिब्बत नीति को नए सिरे से परिभाषित करे जिसमें तिब्बत में होने वाली घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया जाए। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने यह संकेत दिया है कि भारत तिब्बत कार्ड खेलने के लिए तैयार है। पिछले साल नवंबर में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने कश्मीर के मामले में भारत की संवदेनशीलता की तुलना तिब्बत और ताइवान में चीन की संवेदनशीलता से की।

पिछले महीने चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ के भारत आगमन के दौरान भी इस मसले को उठाकर विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख दिखाया है। हालांकि चतुर चीन कुछ दिखावटी रियायतें दे सकता है, लेकिन भारत की मुख्य चिंता 'सीमा विवाद' पर कुछ नही होने वाला। चीन इस विवाद को हल करने का बिल्कुल इच्छुक नहीं है। भारतीय नीति नियंता इसके लिए चीन की उन नीतियों को जिम्मेदार

भारत सरकार के रवैए की सबसे बड़ी असंगतता यह है कि वह खुद चीन के प्रति नरम रवैया अपनाती रही है (1962 में कठोर सबक सीखने के बावजूद) और भारतीय नागरिकों में चीन के इरादों और कार्यों को लेकर संदेह और बढ़ा है।

हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी और एक विकासशील देश भारत पश्चिम की तरफ दिन–ब–दिन और करीब आ रहा है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए नया खतरा बन रहा है। दलाई गुट के साथ भारत की नजदीकी और उन्हें प्रश्रय देने से तिब्बत की स्थिरता एवं विकास को चोट पहुंच रही है।

ठहराते हैं कि बेहतर सीमा समझौतों से उसके सुपर पावर बनने का रास्ता बाधित होगा, लेकिन चीन पर ज्यादा गहरी नजर रखने वाले कुछ लोगों की राय अलग है। चीनी नेता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वे तिब्बती राष्ट्रीयता को दबाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उन्हें आशंका है कि सीमा रेखा के निर्धारण से तिब्बत में भारतीय प्रभाव बढ़ सकता है।

चीन का तर्क साधारण और साफ है: तिब्बत से भारत का ध्यान हटाए रखने के लिए उसे अक्साई चिन और अरुणाचल में उलझाए रखो। भारत भी इसका जवाब अपनी रणनीति में बुनियादी बदलाव लाते हुए दे सकता है। इसके लिए उसे कहना चाहिए सीमा विवाद सिर्फ भारत–चीन के बीच का नहीं बल्कि भारत–तिब्बत–चीन के बीच का मसला है। गौरतलब है कि भारत–चीन वार्ता के दौरान तिब्बत हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है और इसे साफ तौर पर पेश करना चाहिए। यह बात साफ तौर पर जान लेना चाहिए कि ल्हासा तक चीन के जाने का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। इससे भारत की चीन नीति को परेशान करने वाली कई विसंगतियां अपने आप दूर हो जाएंगी।ऐसी पहली विसंगति है तिब्बत में कोई मसला नहीं है, इस बहानेबाजी का असहज राजनीतिक विरोधाभास, जबकि हमने हजारों तिब्बतियों, तिब्बती बौद्ध धर्म के पूरे तंत्र, निर्वासित तिब्बती सरकार और खुद दलाई लामा को शरण दे रखी है। तिब्बत पर भारत के नरम रवैए से चीन इस मामले पर और ढीठ हुआ है।

भारत सरकार के रवैए की सबसे बड़ी असंगतता यह है कि वह खुद चीन के प्रति नरम रवैया अपनाती रही है (1962 में कठोर सबक सीखने के बावजूद) और भारतीय नागरिकों में चीन के इरादों और कार्यों को लेकर संदेह और बढ़ा है। इस खाई से यह सुनिश्चित होता है कि चीन के साथ यदि पर्दे के पीछे कोई समझौता किया जाता है तो देश की जनता इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय अधिकारियों को इस राष्ट्रीय भावना का साफ इजहार करना चाहिए कि तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद अब चीन की लोभी नजरें भारतीय जमीन की ओर हैं।भारत सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ल्हासा में रहने वाले शीर्ष अधिकारी भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह तिब्बत के प्रति दुर्भावना रखता है। तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के जन सुरक्षा ब्यूरो (टीएआरपीएसबी) के प्रमुख लाओ दाकू ने जुलाई से सितंबर, 2010 के बीच तिब्बती इलाकों के दौरे के बाद इंटरनेट पर प्रकाशित तिब्बती भाषा के लेख में लिखा है, "दलाई गुट, अलगाववादियों, आंतरिक एवं बाहरी एवं शत्रु विदेशी ताकतों के बीच गठजोड़ पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है।हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी और एक विकासशील देश भारत पश्चिम की तरफ दिन–ब–दिन और करीब आ रहा है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए नया खतरा बन रहा है। दलाई गुट के साथ भारत की नजदीकी और उन्हें प्रश्रय देने से तिब्बत की स्थिरता एवं विकास को चोट पहुंच रही है। चीन ने तिब्बत में दमन और बढ़ा दिया है जिससे तिब्बतियों में असंतोष बढ़ रहा है। भारत में यह नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि यहां सीमा नीति लगातार कमजोर अवधारणाओं पर आधारित रही है। चीन यह बात जान चुका है कि तिब्बत में उसके भारी बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम और भारतीय सीमा के निकट जन मुक्ति सेना के जवानों को पहुंचा देने के उसके कार्य की बुनियाद कमजोर है। इसलिए भारतीय राजनयिकों के लिए यह उचित समय है कि वे तिब्बत को शर्मिंदगी की जगह एक संपदा के रूप में देखें।

करमापा के कार्यालय ने 'अटकलों पर आधारित आरोपों' का खंडन किया

(फायूल, धर्मशाला, 29 जनवरी, 2011) भारतीय पुलिस द्वारा 17वें करमापा के आवास की तलाशी लगातार तीसरे दिन जारी रही, इस बीच शनिवार को उनके कार्यालय ने औपचारिक रूप से एक बयान जारी कर भारतीय मीडिया के एक वर्ग में आए आरोपों का 'साफ तौर पर' खंडन किया है और इन्हें 'पूरी तरह से अटकलबाजी' बताया है।

बयान में कहा गया है, "हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि करमापा और उनके प्रशासन के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह अटकलों पर आधारित हैं और इनमें सच का कोई आधार नहीं है। हम चीन सरकार के किसी भी अंग से किसी भी तरह के संपर्क की बात को साफतौर पर खारिज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ, भारतीय मीडिया, खासकर टीवी की खबरों में करमापा के चीन से जुड़ाव पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे हाल में यहां तिब्बती धार्मिक नेता के मठ से मिले 5 करोड़ रुपए के प्रकरण ने पूरी तरह से नया मोड़ ले लिया है।

शनिवार को जारी बयान में करमापा के कार्यालय ने कहा है, पुलिस जिस नकदी की जांच कर रही है वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शिष्यों से 'सेवा कार्यों के लिए मिला चंदा' है।

बयान में कहा गया है, "दुनिया भर के मठ अपने भक्तों से विभिन्न रूपों में चंदा हासिल करते रहे हैं, इसमें कुछ भी अचरज करने वाली, नई बात या अनियमितता नहीं है। कोई भी यदि यह कहता है कि इन चंदों का इस्तेमाल अवैध कार्यों के लिए किया गया तो यह अपमानजनक बात है।"

गौरतलब है कि करमापा के पास से करीब 70 लाख भारतीय रुपए के बराबर चीनी मुद्रा जब्त किए जाने की खबरों के बाद भारतीय मीडिया में इस तरह की अटकलबाजी छपनी शुरू हो गई कि करमापा का चीन सरकार से संपर्क है। मीडिया की खबरों में यह अटकलबाजी भी प्रसारित हुई कि धर्मशाला के पास एक मठ बनाने के लिए 'अवैध तरीके से जमीन लेने' के लिए करमापा लामा के कार्यालय द्वारा भारी मात्रा में 'काला धन' इस्तेमाल किया जा रहा है।

करमापा के कार्यालय ने यह स्वीकार किया है कि करमापा के स्थायी आवास के रूप में एक मठ बनाने के लिए 'उपयुक्त जमीन' खरीदने की उनकी योजना है, लेकिन उसने इन आरोपों का खंडन किया है कि इस प्रक्रिया में कहीं से भी कुछ गलत हो रहा है।

बयान में कहा गया है, "दुनिया भर में हम जो कुछ भी सौदा करते हैं वह पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित होता है। इसके अलावा कुछ भी करना उन बौद्ध सिद्धांतों के खिलाफ होगा जिनका हम पालन करते हैं। ग्यालवांग करमापा के कार्यालय ने अपनी जमीन खरीदने की हाल की योजना के बारे में संबंधित भारतीय एजेंसियों को पूरी जानकारी दी थी। संभावित जगहों का उपयुक्त सरकारी कार्यालयों द्वारा मूल्यांकन

तिब्बत के सुर्फू से सिर्फ 14 साल की अवस्था में जनवरी 2000 में साहस कर भारत चले आने के बाद से ही करमापा लामा दलाई लामा के निर्वासन केंद्र और निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्र धर्मशाला में स्थित ग्यूतो तांत्रिक मठ विश्वविद्यालय के सबसे ऊपरी मंजिल पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं।

स्थानीय मठ के एक भिक्षु थुपतेन सेरिंग ने कहा, "हम तिब्बती गद्दार नहीं हैं, जैसा कि कुछ टीवी चैनल हमारी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने धार्मिक नेताओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं जिसने हमने सदगुण सीखे हैं, पाप नहीं। अभी जांच चल ही रही है और इस बीच हमारे नेता को चीनी जासूस और गद्दार साबित करने की कोशिश जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं है।"

किया गया और उसे मंजूरी दी गई। यह परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही शुरू होनी है।"

करमापा के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "हम जहां तक संभव होगा और जितनी जानकारी उपलब्ध होगी वह मुहैया कराएंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता चल रही जांच में सहयोग करना है।" तिब्बत के सुर्फू से सिर्फ 14 साल की अवस्था में जनवरी 2000 में साहस कर भारत चले आने के बाद से ही करमापा लामा दलाई लामा के निर्वासन केंद्र और निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्र धर्मशाला में स्थित ग्यूतो तांत्रिक मठ विश्वविद्यालय के सबसे ऊपरी मंजिल पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं।

हालांकि, करमापा को भारत में राजनीतिक शरण दी गई, लेकिन अत्यंत सम्मानित बौद्ध नेता पर शुरू से ही लगातार खुफिया एजेंसियों की नजर रहती है और उनके अस्थायी ठिकाने पर चौबीसों घंटे पुलिस मौजूद रहती है।

करमापा लामा के बारे में आई खबरों के बारे में सुनकर निर्वासित तिब्बती समुदाय और बौद्ध संप्रदाय के लोग क्षुब्ध हैं और उनका कहना है कि उनके धार्मिक गुरू के बारे में इस तरह की मीडिया अटकलबाजी कि वे एक चीनी जासूस हैं, पूरी तरह से 'हास्यास्प्रद' और बेवजह 'सनसनी' पैदा करने की कोशिश है।

स्थानीय मठ के एक भिक्षु थुपतेन सेरिंग ने कहा, "हम तिब्बती गद्दार नहीं हैं, जैसा कि कुछ टीवी चैनल हमारी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने धार्मिक नेताओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं जिसने हमने सदगुण सीखे हैं, पाप नहीं। अभी जांच चल ही रही है और इस बीच हमारे नेता को चीनी जासूस और गद्दार साबित करने की कोशिश जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं है।"

शनिवार को ही एक संवाददाता सम्मेलन में निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेनपा सेरिंग ने कहा कि करमापा लामा के चीन सरकार से जुड़े होने की मीडिया अटकलों का 'कोई आधार' नहीं है। उन्होंने कहा कि तिब्बती संसद और कशग, दोनों इस मामले की सचाई को सामने लाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। खबरों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डी.एस. मनहास ने कहा है, "प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां इस जाचं में शामिल हैं क्योंकि इस बात की जांच जरूरी है कि इतनी मुद्रा कहां से आई और मठ में इतनी भारी राशि रखने में किन नियमों का उल्लंघन किया गया।" दूसरी तरफ देहरादून से बुलाए गए करमापा के सचिव गोम्पो सेरिंग के आवास पर भी शनिवार को छापा डाला गया। खबरों में दावा किया गया है कि सेरिंग के आवास से भी 4 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की गई।

खबरों के अनुसार इन एजेंसियों ने इसके पहले गुरुवार को एक स्थानीय कारोबारी के.पी. भारद्वाज के यहां छापा डालकर उनसे एक करोड़ रुपए बरामद किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह रकम करमापा ट्रस्ट द्वारा यहां जमीन खरीदने के लिए भुगतान की गई थी।